एम. एम. पुंछी, जे.के समक्ष

कमल देव,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी।

1986 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 390

14 मई 1986

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1947 का द्वितीय) - धारा 5(1)(ई) - लोक सेवक पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के रूप में आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया - किसी विशेष स्थान पर तैनात रहते हुए अर्जित की गई संपत्ति - स्थित संपत्ति का हिस्सा कार्यालय का स्थान जबकि अन्य बाहर स्थित हैं–कार्यालय का स्थान–क्या अपराध के विचारण के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारित करता है।

माना गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) को पढ़ने से पता चलेगा कि आपराधिक कदाचार के अपराध का संबंध कार्यालय की अवधि से है। यह इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि यह कार्यालय का स्थान है जो सरकारी कर्मचारी के कदाचार का निर्धारण करेगा। केवल उसके कार्यालय के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपनी आय का ज्ञात स्रोत निर्धारित कर सकता है और जो वर्तमान में उसके कब्जे में या उसकी ओर से किसी के कब्जे में या उसके कार्यालय की अवधि के दौरान किसी भी समय उसके पास रही है या उसकी ओर से किसी के पास रही, तो इसे अपेक्षाकृत रूप से लोक सेवक के पद की अवधि के साथ देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में कार्यालय का स्थान महत्व रखता है, क्योंकि यह उस क्षेत्राधिकार का निर्धारण करेगा जिसमें कदाचार के अपराध की सुनवाई की जाएगी।

(पैरा 4)

सीआरपीसी की धारा 401 के तहत याचिका धारा 482 सी.आर.पी. सी के साथ पठित। श्री पी. सी. नरियाला, विशेष न्यायाधीश, अम्बाला के 26 फरवरी, 1986 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए पी.सी. ने आदेश दिया कि आरोपी कमल देव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 धारा 5(1)(बी) के तहत धारा 5(2) के तहत दंडनीय अपराध के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया जाता है।

आवेदक की ओर से बैज नाथ शर्मा, अधिवक्ता और कपिल शर्मा, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से एस.पंवार, ए.ए.जी., हरियाणा।

निर्णय

एम. एम. पुंछी, जे. (मौखिक):-

(1) सतर्कता जांच के दौरान, यह पता चला कि याचिकाकर्ता कमल देव के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी और वह इसका संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। इसने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(ई) के दायरे में ला दिया। तदनुसार, एक एफ.आई.आर. 2 अक्टूबर, 1984 को पी.एस.विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश, अंबाला की अदालत में उचित समय पर एक चालान पेश किया गया था।

(2) याचिकाकर्ता ने क्षेत्राधिकार पर आपत्ति ली। उनके मुताबिक, उनका पूरा सर्विस करियर चंडीगढ़ में गया हालाँकि, वह हरियाणा सरकार के कर्मचारी थे। इसके अलावा, उनका तर्क यह था कि उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक, कथित तौर पर चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में थी, जबकि वह चंडीगढ़ में कार्यरत थे। इस प्रकार, यह आग्रह किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता के साथ आपराधिक कदाचार तब किया गया जब उसे चंडीगढ़ में पोर्ट किया गया था, तो यह उसका कदाचार जो आरोप का विषय है, न कि प्रत्येक संपत्ति है। पंचकुला (हरियाणा) में स्थित है। विद्वान विशेष न्यायाधीश, अंबाला ने अपने आदेश 26 फरवरी, 1986 द्वारा ऐसी याचिका को खारिज कर दिया जिसने वर्तमान याचिका को जन्म दिया, जिसे अब संशोधित करने की मांग की है।

(3) प्रासंगिक दंड धारा जो कि आकर्षित होती है वह इस प्रकार है: -

"5. सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में आपराधिक कदाचार–(1) एक लोक सेवक के बारे में कहा जाता है कि उसने आपराधिक कदाचार का अपराध किया है–

X X X X

(ई) वह, या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति, उसके कार्यालय की अवधि के दौरान किसी भी समय, उसके कब्जे में है या रहा है, जिसके लिए लोक सेवक आर्थिक संसाधनों या अनुचित संपत्ति का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है। अपनी आय के ज्ञात स्रोत पर ध्यान दें।"

(4) आपराधिक कदाचार के अपराध का कमीशन उसके कार्यालय की अवधि से जुड़ा हुआ है। यह आपस में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि यह कार्यालय का स्थान है जो उसके कदाचार के कमीशन का स्थान निर्धारित करेगा।

केवल उसके कार्यालय के माध्यम से ही एक कार उसकी आय के ज्ञात स्रोत का निर्धारण करती है और क्या उसकी संपत्ति जो वर्तमान में उसके कब्जे में है या उसकी ओर से किसी के कब्जे में है, या उसके कार्यालय की अवधि के दौरान किसी भी समय उसके कब्जे में रही है या किसी की ओर के, तो यह अपेक्षाकृत उसके कार्यालय की अवधि के साथ जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में, कार्यालय का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह उस क्षेत्राधिकार का निर्धारण करेगा जिसमें आपराधिक कदाचार का अपराध विचारणीय होगा। इस प्रकार, तत्काल मामले में, मेरा विचार है कि चंडीगढ़ में विशेष न्यायाधीश को याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था।

(5) मामले को दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर, अन्यथा भी, मामले की सुनवाई चंडीगढ़ में करना उचित होगा। यद्यपि यह माना जा सकता है कि आपराधिक कदाचार का अपराध चंडीगढ़ में किया गया था, फिर भी यह वैध रूप से कहा जा सकता है कि इसके परिणाम चंडीगढ़ के बाहर के स्थानों पर हुए ताकि संहिता की धारा 179 और 180 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। आपराधिक कार्यवाही पुनः. इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के बिना, कम से कम यह कहा जा सकता है कि दोनों न्यायालयों, अर्थात्, अंबाला और चंडीगढ़ में उनका अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, दोनों में से, न्याय के हित में यह उचित होगा कि मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष की जाए।

(6) इस प्रकार, उपरोक्त दोनों विचारों के आधार पर, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता का मुकदमा विशेष न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष चलाया जाएगा। तदनुसार, चालान को विशेष न्यायाधीश, अंबाला द्वारा विशेष न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए अभियोजक को वापस कर दिया जाएगा। मैं इसे विशेष न्यायाधीश, चंडीगढ़ को स्थानांतरित करने का आदेश देता हूं। पक्षों को उनके वकील के माध्यम से 12 जून, 1986 को विद्वान विशेष न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

H.S.B.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(*Trainee Judicial Officer*)

करनाल, हरियाणा